भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
13.12.2023 के
अतारांकित प्रश्न सं. 1674 का उत्तर

आकांक्षी जिलों में रेल सुविधाएं

1674. श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) रेलवे द्वारा मालवा-निमाड़ क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी भावी कार्य योजना क्या है;
(ख) खरगोन-बड़वानी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत जनजातीय बहुल क्षेत्र में रेल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रेलवे किन परियोजनाओं पर विचार कर रहा है;
(ग) क्या निमाड़-खरगोन-बड़वानी-धार-अलीराजपुर क्षेत्र को जोड़ने के लिए कोई विशेष रेल परियोजना प्रस्तावित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) आकांक्षी जिलों में रेल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

s.k

आकांक्षी जिलों में रेल सुविधाओं के संबंध में दिनांक 13.12.2023 को लोक सभा में श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल के अतारांकित प्रश्न सं. 1674 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (घ): रेल परियोजनाओं को क्षेत्रीय रेल-वार स्वीकृत किया जाता है न कि राज्य-वार/ जिला-वार/क्षेत्र-वार/निर्वाचन क्षेत्र-वार क्योंकि भारतीय रेल की परियोजनाएं राज्य की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं। बहरहाल, मालवा निमार क्षेत्र में रेल-संपर्क मुहैया कराने हेतु रेलवे द्वारा एक बड़ी परियोजना इंदौर बुदनी नई लाइन (205 किलोमीटर) कार्यान्वित की जा रही है। यह परियोजना मध्य प्रदेश के इंदौर, देवास और सीहोर जिलों से होकर गुजरती है।

01.04.2023 की स्थिति के अनुसार, मालवा निमार और जनजातीय बहुल क्षेत्रों सहित मध्य प्रदेश में पूर्णतः/अंशतः स्थित 77,798 करोड़ रुपए की लागत पर कुल 5,539 किलोमीटर लंबाई की 32 रेल अवसंरचना परियोजनाएं (08 नई लाइन, 02 आमान परिवर्तन तथा 22 दोहरीकरण) योजना बनाने/अनुमोदन/निष्पादन के चरण में हैं। इनमें से मार्च, 2023 तक 1,557 किलोमीटर लंबी लाइन को चालू किया जा चुका है और 31,111 करोड़ रुपए का व्यय उपगत किया जा चुका है। इनमें शामिल हैं-

- **32,226 करोड़ रुपये की लागत पर कुल 1,979 किलोमीटर लंबाई की 08 नई लाइन परियोजनाएं, जिनमें से मार्च, 2023 तक 400 किलोमीटर लंबी लाइन को चालू कर दिया गया है और 8,611 करोड़ रुपये का व्यय उपगत किया गया है।**

- **9,297 करोड़ रुपये की लागत पर कुल 780 किलोमीटर लंबाई की 02 आमान परिवर्तन परियोजनाएं, जिनमें से मार्च, 2023 तक 283 किलोमीटर लंबाई को चालू कर दिया गया है और 4,040 करोड़ रुपये का व्यय उपगत किया गया है।**

s.k

- **36,275 करोड़ रुपये की लागत पर कुल 2780 किलोमीटर लंबाई की 22 दोहरीकरण परियोजनाएं, जिनमें से मार्च, 2023 तक 874 किलोमीटर लंबाई को चालू कर दिया गया है और 18,460 करोड़ रुपये का व्यय उपगत किया गया है।**

मध्य प्रदेश राज्य में रेल परियोजनाएं भारतीय रेल के उत्तर मध्य रेल, पश्चिम मध्य रेल, पूर्व मध्य रेल, पश्चिम रेल, मध्य रेल, दक्षिण मध्य रेल और दक्षिण पूर्व मध्य रेल के अंतर्गत आती हैं। भारतीय रेल की वेबसाइट पर रेल परियोजनाओं की निधि आबंटन और परियोजना-वार और जोनवार व्यय सहित अन्य ब्यौरा सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है।

वर्ष 2014 से, अवसंरचना परियोजनाओं के लिए बजट आबंटन और तद्नुरूप उनके चालू होने में काफी वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश राज्य में पूर्णतः/अंशत: स्थित अवसंरचना परियोजनाओं एवं संरक्षा कार्यों के लिए औसत वार्षिक बजट आबंटन इस प्रकार है:-

अवधि	औसत परिव्यय	2009-14 के दौरान औसत आबंटन की तुलना में प्रतिशत अधिकता
2009-14	632 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष	-
2023-24	13,607 करोड़ रुपये	2053% अधिक

2014-24 के दौरान, मध्य प्रदेश राज्य में पूर्णतः/अंशत: स्थित कुल 1741 किलोमीटर रेलखंड (293 किलोमीटर नई लाइन, 636 किलोमीटर आमान परिवर्तन तथा 812 किलोमीटर दोहरीकरण) को 193.44 किलोमीटर प्रतिवर्ष की औसत दर से चालू किया गया है जो 2009-14 के दौरान चालू करने की वार्षिक औसत (29 किलोमीटर प्रतिवर्ष) से 567% अधिक है।

जनजातीय बहुल क्षेत्रों में रेल-संपर्क मुहैया कराने के लिए खांडवा-धार बरास्ता खरगोन और बरवनी (260 किलोमीटर) नई लाइन को स्वीकृत किया गया है तथा क्षेत्र सर्वेक्षण कार्य को पूरा कर लिया गया है। 1794 करोड़ रुपये की लागत पर छोटा उदेपुर-धार (157 किलोमीटर) नई लाइन परियोजना के हिस्से के तौर पर धार-अलीराजपुर खंड (109 किलोमीटर) पर कार्य शुरू किया गया है।

s.k

रेल परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वानिकी स्वीकृति, अतिलंघनकारी जनोपयोगी सेवाओं (भूमिगत और भूतल के ऊपर, दोनों) को स्थानांतरित करना, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भूविज्ञानी और स्थलाकृतिक परिस्थितियां, परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण परियोजना स्थल विशेष के लिए एक वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या, अप्रत्याशित परिस्थितियों का प्रकट होना जैसे भूकम्प, अतिवृष्टि, कार्यरत एजेंसियों/ठेकेदारों की स्थिति एवं दशा आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है और ये सभी कारक परियोजना को पूरा करने के समय को प्रभावित करते हैं।

****

s.k